1. ज्वारीय तरंगें ओडिशा के गांव के एक हिस्से को बहा ले गईं

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, **'रामायापल्ली'** जो ओडिशा का एक गांव है पिछले 14 वर्षों से ज्वारीय तरंगों के खतरे का सामना कर रहा है, जिससे बंगाल की खाड़ी खतरनाक तरीके से मुख्यभूमि की ओर आ रही है।

Vanishing village: The sea surge has resulted in submergence of the beach in Ramayapalli.Special arrangement

ज्वारीय तरंगों के बारे में जानकारी

- ज्वार-भाटे को महासागर के जल के क्रमशः बढ़ने और घटने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह निम्न के संयुक्त प्रभाव से होता है :
    a. सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से
    b. चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से
    c. पृथ्वी के चक्रण से

ज्वार-भाटे के प्रकार

आवृत्ति पर आधारित ज्वार-भाटे

a. अर्धदैनिक ज्वार-भाटा
b. दैनिक ज्वार-भाटा
c. मिश्रित

पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित ज्वार-भाटा

a. वृहद् ज्वार-भाटा
b. लघु ज्वार-भाटा

2. स्पिनर डॉल्फिन

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- DTE)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, स्पिनर डॉल्फिन का शव बहकर ओडिशा के बंदरगाह शहर पारादीप के तट पर बहकर आ गया जो भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क में स्थित है।

स्पिनर डॉल्फिन के बारे में जानकारी

- स्पिनर डॉल्फिन (स्टेनेला लांगीरोस्ट्रिस) एक छोटी डॉल्फिन है जो पूरी दुनिया के उष्णकटिबंधीय जलों के तटों पर पाई जाती है।
- यह अपनी कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें यह अपने अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ चक्रण करती है जब वह हवा में उछलती है।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN लाल सूची: कम चिंता
- CITES: परिशिष्ट I
- CMS (संक्रमणीय पक्षियों पर संधि): परिशिष्ट II

संबंधित सूचना

इर्रावड्डी डॉल्फिनों के बारे में जानकारी

- इर्रावड्डी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में और तीन नदियों में पाई जाती हैं: एयेयारवाडी (म्यांमार), महाकाम (इंडोनेशियाई बोर्नियो) और मेकांग।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN लाल सूची: संकटग्रस्त
- CITES: परिशिष्ट I
- CMS (संक्रमणीय पक्षियों पर संधि): परिशिष्ट I
- वन्यजीवन संरक्षण कानून, 1972: अनुसूची I

हिंद-प्रशांत बॉटलनोज़ डॉल्फिन

- हिंद-प्रशांत डॉल्फिन सामान्यतया हिंद महासागर, दक्षिणपूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के छिछले तटीय जलों में पाई जाती हैं।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN लाल सूची: लगभग संकटग्रस्त
- CITES: परिशिष्ट II

हिंद महासागर कूबड़ वाली डॉल्फिन

- हिंद महासागर की कूबड़ वाली डॉल्फिन दक्षिण अफ्रीका से भात तक हिंद महासागर में पाई जाती हैं।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN लाल सूची: संकटग्रस्त
- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीवन संरक्षण कानून, 1972: अनुसूची I

3. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (PMFME) योजना

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- कृषि, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (PMFME) योजना के एक वर्ष पूरे हो गए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (PM-FME योजना) के बारे में जानकारी

- इसे **आत्म निर्भर भारत अभियान** के तहत शुरू किया गया है।
- यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

लक्ष्य

- इस योजना का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के गैरसंगठित क्षेत्र में वर्तमान व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतियोगिता को उन्नत करना है। साथ ही क्षेत्र के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना और किसान उत्पादक संगठनों, स्वयंसेवी समूहों, और पूरी मूल्य श्रृंखला में उत्पादक सहकारी समितियों को समर्थन प्रदान करना है।
- PM-FME योजना के अंतर्गत, राज्यों ने जिलों के खाद्य उत्पादों की पहचान कर ली है, जिसके लिए वर्तमान क्लस्टरों और कच्चे मालों की उपलब्धता का ध्यान रखा गया है।
- इस योजना का क्रियान्वयन 2020-21 से 2024-25 के बीच में पांच वर्षों के दरमियान किया जाएगा।

GIS ODOP डिजिटल मानचित्र

- GIS ODOP भारत का डिजिटल मानचित्र सभी राज्यों के ODOP उत्पादों का विवरण उपलब्ध कराता है और हितधारकों को सुगमता प्रदान करता है।
- डिजिटल मानचित्र में आदिवासी, SC, ST और महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संसूचक भी हैं।
- यह हितधारक को उनके मूल्य श्रृंखला विकास के लिए लगातार प्रयास करने के वास्ते सक्षम बनाएगा।

उद्देश्य:

- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा वित्त तक पहुँच में वृद्धि।
- लक्षित उद्यमों के राजस्वों में वृद्धि।
- खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का उन्नत अनुपालन।
- समर्थन प्रणालियों की क्षमताओं को मजबूती।
- गैरसंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण।
- महिला उद्यमियों और महत्वाकांक्षी जिलों पर विशेष जोर।
- आदिवासी जिलों में छोटे वन उत्पाद पर जोर।

योजना के पीछे तर्क:

- भारत का गैरसंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 25 लाख इकाईयों के साथ लगभग 74% रोजगार में योगदान देता है।
- इनमें से लगभग 66% इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं जो ग्रामीण परिवारों को जीवनयापन उपलब्ध करा रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में उनके प्रवसन को न्यूनतम कर रहे हैं।
- ये इकाईयों मोटे तौर पर सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में आते हैं।
- ये उद्यम अपने दैनिक प्रचालनों में कई चुनौतियों का सामना करते हैं जैसे किः
    - कोषों और संस्थागत ऋण की कमी।
    - आधुनिक तकनीक और उपकरणों तक खराब पहुँच यद्यपि इनके पास ये उपलब्ध भी हैं तो प्रशिक्षण की कमी से उनके उत्पादन नीचे आ जाता है।
    - विपणन और ब्रांडिंग कौशल की कमी।
    - मूलभूत जागरूकता और गुणवत्ता नियंत्रणों की कमी।

4. शिक्षा प्लस के लिए संयुक्त जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) 2019-20

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- शिक्षा, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल में भारत में विद्यालय शिक्षा पर शिक्षा प्लस के लिए संयुक्त सूचना प्रणाली (UDISE+) पर एक रिपोर्ट जारी की।

शिक्षा प्लस के लिए संयुक्त जिला सूचना प्रणाली के बारे में जानकारी

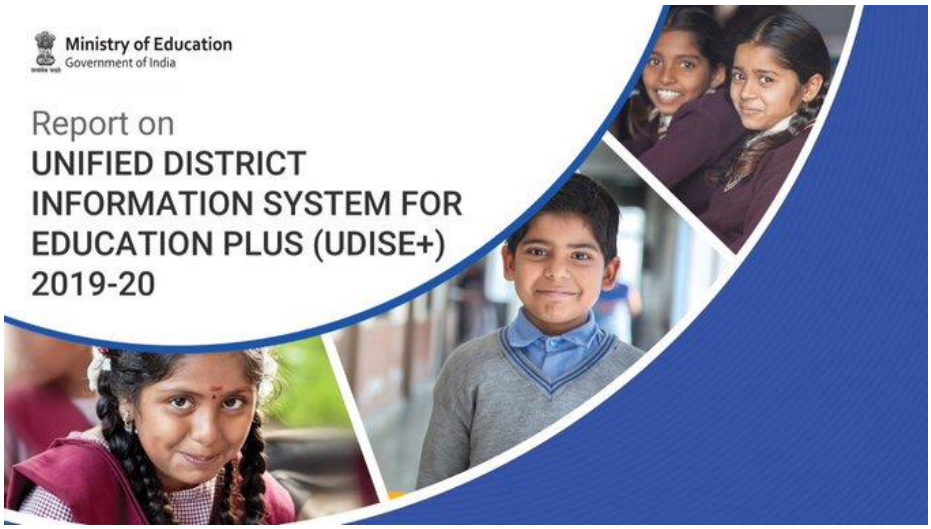

- विद्यालयों से ऑनलाइन डाटा संग्रहण की UDISE+ प्रणाली को वर्ष 2018-19 में विकसित किया गया था जिसका उद्देश्य पेपर के प्रारूप में हाथ से डाटा भरने से संबंधित मामले से पार पाना है और साथ ही प्रखंड अथवा जिला स्तर पर इसकी फीडिंग करना है, जो 2012-13 से UDISE डाटा संग्रहण प्रणाली में चल रहा है।
- वर्तमान प्रकाशन 2019-20 के संदर्भ वर्ष के UDISE+ डाटा से संबंधित है।

प्रमुख खास बातें

- यह रिपोर्ट विद्यालय शिक्षा, छात्र अध्यापक अनुपात, बालिकाओं के नामांकन के सभी स्तरों पर GER में सुधार दर्शा रहा है।

सकल नामांकन अनुपात

विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सुधार हुआ है।

- सकल नामांकन अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर पर 89.7% तक बढ़ गया (87.7% से), प्राथमिक स्तर पर 97.8% तक पहुँच गया (96.1% से), माध्यमिक स्तर पर 77.9% तक पहुंच गया (76.9% से), और उच्च माध्यमिक स्तर पर 51.4% तक पहुँच गया (50.1% से)। यह आंकड़े 2019-20 के हैं (तुलना 2018-19 से)।
- बालिकाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर पर 90.5% तक पहुंच गया (88.5% से), प्राथमिक स्तर पर 98.7% तक पहुँच गया (96.7% से), माध्यमिक स्तर पर 77.8% तक पहुंच गया (76.9% से) और उच्च माध्यमिक स्तर में 52.4% तक पहुंच गया (50.8% से)। यह आंकड़े 2019-20 के हैं (2018-19 की तुलना में)।

दिव्यांग छात्रों का नामांकन

- दिव्यांग छात्रों का नामांकन 2018-19 की तुलना में 6.52% बढ़ा।

छात्र अध्यापक अनुपात (PTR)

छात्र अध्यापक अनुपात (PTR) विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों में सुधरा है।

- 2019-20 में प्राथमिक के लिए PTR 26.5 हो गया, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक के लिए PTR 18.5 और उच्च माध्यमिक के लिए PTR 26.1 हो गया।
- 2019-20 में माध्यमिक के लिए PTR 18.5 था जबकि 2012-13 में यह 29.7 था।
- 2019-20 में उच्च माध्यमिक के लिए PTR 26.1 हो गया जबकि 2012-13 यह 39.2 था।

इंटरनेट की सुविधाएं

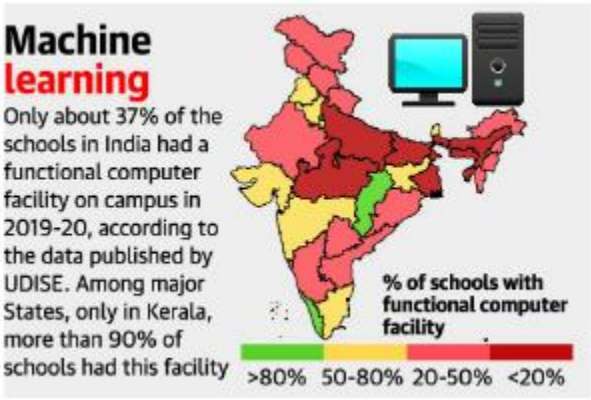

- कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद होने की स्थिति से समाप्त अकादमिक वर्ष में भारत के केवल 22% विद्यालयों में इंटरनेट सुविधाएं हैं।
- सरकारी विद्यालयों के बीच में, 2019-20 में 12% से कम विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा थी, जबकि 30% से भी कम के पास कार्यात्मक कम्प्यूटर सुविधाएं थीं।
- इससे महामारी के दौरान विद्यालयों को उपलब्ध डिजिटल शिक्षा विकल्पों के प्रकार प्रभावित हुए हैं, साथ ही आने वाले दिनों में संकर शिक्षण के लिए योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं।

5. 'इंद्रजाल'- भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा, स्रोत- AIR)

खबरों में क्यों है?

- हैदराबाद आधारित तकनीकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम जिसे "इंद्रजाल" कहते हैं, को डिजाइन और विकसित किया है।

इंद्रजाल के बारे में जानकारी

- इस ड्रोन रक्षा डोम में किसी हवाई खतरे से 1000-2000 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल को स्वायत्त तरीके से संरक्षित करने की क्षमता है जिसके लिए वह मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs), घूमने वाले हथियारों, और लो रडार क्रास सेक्शन (RCS) लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों को आकलित करके उनपर कार्रवाई करता है।

इंद्रजाल की खास विशेषताएं

- वास्तविक समय परिस्थिति वाली जागरूकता
- एकीकृत और बुद्धिमान जालीदार नेटवर्क

- एकीकृत ऑल करेंट हथियार स्यूट और अवसंरचना
- बाधारहित निर्माण के लिए मधुमक्खी के छत्ते की कोशिका संरचना
- 9-10 तकनीकों का समन्वित संयोजन
- 24×7 सतत और स्वायत्त निगरानी, कार्रवाई और ट्रैकिंग

6. ZyCov-D टीका

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, अहमदाबाद आधारित जाइडस कैडिला ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को आवेदन करके अपने कोविड-19 टीके ZyCov-D के लिए आपातकालीन प्रयोग अधिकार मांगा है।
- यदि विनियामक द्वारा स्वीकृति किया जाता है तो ZyCov-D विश्व का पहला SARS-CoV-2 के साथ संक्रमण के खिलाफ डीएनए टीका होगा।

ZyCov-D टीके के बारे में जानकारी

- इसे केंद्रीय सरकार के बायोतकनीक विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की सहायता से विकसित किया गया है।

विशेषताएं

- यह एक प्लाज़मिड डीएनए टीका है- अथवा एक टीका है एक अनुवांशिक इंजीनियर्ड, गैरप्रतिकृति वाले वर्जन का प्रयोग करता है जो प्लाज़मिड कहे जाने वाले डीएनए अणु का प्रकार है।
- इस मामले में प्लाज़मिडों को इस निर्देश के साथ कोड किया जाता है कि वे SARS-CoV-2 की स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करें जो कोविड-19 को पैदा करने वाला कोरोनावायरस है।
- टीकाकरण प्राप्तकर्ता के शरीर में कोशिकाओं को कोड देते हैं, जिससे वे वायरस के स्पाइकी बाहरी स्तर को बनाना आरंभ कर दें। प्रतिरक्षा प्रणाली से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसे खतरे के रूप में पहचानें और प्रतियुत्तर में प्रतिपिंड उत्पन्न करें।

बिना सुई वाला एप्लीकेटर

- यह टीका फार्माजेट के साथ आएगा, यह एक सुईरहित एप्लीकेटर है जो दर्दरहित त्वचा के अंदर टीके की पहुँचाना सुनिश्चित करेगा।

क्षमता

- इसकी प्राथमिक क्षमता 66.6% है।

7. कैबिनेट ने रु. 3.03 ट्रिलियन की बिजली डिस्कॉम सुधार योजना स्वीकृति की

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अवसंरचना (ऊर्जा क्षेत्र), स्रोत- AIR)

खबरों में क्यों है?

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को मार्क्यू रु. 3.03 ट्रिलियन बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) सुधार योजना को स्वीकृति दे दी, जिसमें केंद्र की साझीदारी रु. 97,631 करोड़ रहेगी।

डिस्कॉम सुधार योजना के बारे में जानकारी

- यह सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी हुई बिजली वितरण क्षेत्र योजना है। यह 2025-26 तक लागू रहेगी। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021 में की गई थी।
- यह योजना एकीकृत बिजली विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसे कार्यक्रमों का विलय करती है।

- इस योजना का लक्ष्य निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर सभी डिस्कॉम/बिजली विभागों की प्रचालनात्मक क्षमताओं और वित्तीय सततता में सुधार करना है जिसके लिए आपूर्ति अवसंरचना को मजबूती देने के लिए डिस्कॉम को सशर्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

लक्ष्य

- इस योजना का लक्ष्य भारत के औसत समग्र तकनीकी और व्यावसायिक हानि को वर्तमान स्तर 21.4% से घटाकर 12-15% तक करना है और धीरे से बिजली की कीमत और जिस मूल्य पर इसे आपूर्ति किया जाता है, के बीच के घाटे को 2024-25 तक शून्य करना है।
- इन सुधारों का उद्देश्य जिली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करना है।
- इस योजना में पूरे वितरण क्षेत्र में एक अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग पारितंत्र प्रणाली शामिल है- यह बिजली फीडरों से शुरू होकर उपभोक्ता स्तर तक जाएगी, जिसमें 250 परिवार शामिल होंगे। साथ ही, हानि कटौती के उपाय जैसे कृषीय और ग्रामीण परिवार उपभोग के लिए अलग फीडर भी लगाए जाएंगे।

क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी

- राज्य द्वारा संचालित बिजली वित्त निगम (PFC) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है।

महत्व

- यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि भारत सतत विकास लक्ष्य (SDG7) में अग्रणी है जिसका लक्ष्य सभी के लिए वहनीय, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच को सुनिश्चित करना है।

नोट:

- केंद्र सरकार कई उपायों पर कार्य कर रही है जिसमें जीवाश्म ईंधनों के साथ इथेनॉल का मिश्रण करना, हरित गतिमयता, बैटरी भंडारण और हरित हाइड्रोजन शामिल हैं जिसका उद्देश्य 2015 में फ्रांस में हुई संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन सम्मेलन COP-21 में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं को सुगम बनाकर प्रदूषण को कम करना है।

8. आंध्र ने 2021-24 के लिए IT नीति लागू की

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र, स्रोत- बिज़ीनेस स्टैंडर्ड)

खबरों में क्यों है?

- आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल में अपनी नई आंध्र प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021-24 का अनावरण किया है।

2021-24 के लिए IT नीति के बारे में जानकारी

- नई IT नीति प्रोत्साहन राशि के वितरण को प्रतिबद्ध प्रत्यक्ष रोजगार से जोड़ती है जिससे सार्वजनिक कोषों की प्रभावी उपयोगिता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- पूर्व की IT नीति से अलग हटते हुए, नई नीति स्टार्टअप्स जैसे प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस, निवेशकों तक पहुँच, सलाहकारों, प्रतिभा के जमाव, वेंचर पूंजी के द्वारा कोष, निजी इक्विटी फर्म और अन्य सामान्य तौर पर साझा सेवाओं को चर परिवर्तनीय आधार पर शुरू से आखिर तक सहायता प्रदान करती है।
- अगले तीन वर्षों के दौरान इस नीति से 55,000 से ज्यादा नौकरियां सृजित होने की संभावना है।
- **यह नीति मार्च 31, 2024 तक प्रभावी रहेगी।**

अन्य पहल

- सरकार IT और अत्याधुनिक उभरती हुआ तकनीकों में राष्ट्रीय प्रतिभा के जमाव के अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में राज्य के विकास के लिए विशाखापत्तनम में एक IT इमर्जिंग टेक्नोलॉजीस रिसर्च यूनीवर्सिटी की स्थापना करेगी।
- यह विश्वविद्यालय राज्य के हित के क्षेत्रों में उभरती हुई तकनीकों के प्रयोग में अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर जोर देगा। **उच्च गति के इंटरनेट, छह वर्कस्टेशनों और जरूरी सॉफ्टवेयरों के साथ ग्राम पंचायत स्तर** पर डिजिटल पुस्तकालयों और कार्यस्थलों के गठन का प्रस्ताव है।

9. आत्मनिर्भर कृषि ऐप

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- कृषि, स्रोत- AIR)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, सरकार ने कदम उठाने योग्य कृषीय अंतर्दृष्टियों और पूर्व मौसम चेतावनी को किसानों को उपलब्ध कराने के लिए "आत्मनिर्भर कृषि ऐप" उतारा है।

आत्मनिर्भर कृषि ऐप के बारे में जानकारी

- यह एक एंड्रोयड और विंडोज़ वर्जन है जो किसानों, स्टार्टअप्स, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्वयंसेवी समूहों और गैर सरकारी संगठनों को मुफ्त में 12 भाषाओं में उपलब्ध है।

लक्ष्य

- मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के स्वास्थ्य, नमी, मौसम और जल तालिका से संबधित आंकड़ों को एकत्र करके निजी अंतर्दृष्टि को उत्पन्न करने के लिए विश्लेषित किया जाता है।
- यह ऐप किसानों और उसके खेतों के लिए जरूरी आंकड़ों को एक साथ लाता है। इसे विभिन्न एजेंसियों और भारत सरकार के विभागों से एकत्रित किया जाता है।
- जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए ऐप खेत की भू-स्थित पर निर्भर रहता है।
- यह वर्तमान की जमीनी वास्तविकताओं के अनुसार विशिष्ट रूप से किसानों के साथ संवाद करके कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) को सहायता प्रदान करेगा।

चरण:

ऐप की संकल्पना पांच चरणों में की गई:

a. आंकड़ों को एकत्रित करना
b. केंद्रीकृत अंतर्दृष्टि का निर्माण करना
c. स्थानीय विशेषज्ञता समर्थित अन्योन्यक्रियाओं और अंतर्दृष्टियों को सक्षम बनाना

d. मशीन लर्निंग अनुमानों को प्राप्त करना
e. सतत सुधार

कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में

- ये भारत में कृषीय विस्तार केंद्र हैं जो सामान्य तौर पर स्थानीय कृषीय विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं।
- ये केंद्र भारतीय कृषीय अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच में सर्वोच्च जुड़ाव के रूप में कार्य करते हैं और ये कृषीय अनुसंधान का व्यवहारिक और स्थानीयकृत तरीके से प्रयोग करते हैं।
- सभी KVKs पूरे भारत में 11 में से एक कृषीय तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों (ATARIs) के अधिकारक्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।

खबरों में यह भी

राजधानी को जल्दी ही कोविड से लड़ाई के लिए कलर कोड वाली प्रतियुत्तर प्रणाली मिलेगी

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- दिल्ली को जल्दी ही कोविड-19 से लड़ाई और नियंत्रित करने के लिए एक कलर कोडेड प्रतियुत्तर प्रणाली मिलेगी जिसमें प्रत्येक रंग लॉकडाउन सहित पहले से निर्धारित कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करेगा।

खबरों में और भी है

- प्रतियुत्तर प्रणाली को चार प्रकार के अलर्ट में विभाजित किया गया है- पीला, एम्बर, नारंगी और लाल- जिनमें से प्रत्येक टेस्ट पॉजिटिविटी दर, नये मामलों, और बेडों के भरे होने पर आधारित होगा।
- पीला सबसे निचले स्तर का अलर्ट होगा जबकि लाल सबसे ऊंचे स्तर का।
- इसलिए, यदि अलर्ट पीला है, रोक एथवा लॉकडाउन सहित सरकार द्वारा किए गए उपाय लाल की तुलना में कम गंभीर होंगे, जो ज्यादा कड़े उपायों का कारण बनेगा।
- सरकार कार्रवाई करेगी जिसमें अलग-अलग तीव्रता के लॉकडाउन, साथ ही चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करना शामिल होगा। यह अलर्ट के स्तर पर निर्भर होगा।